web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार, 02 अप्रैल 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 183

मार्च 2022 में कुल जीएसटी संग्रह सबसे ज्यादा, पूर्व के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जनवरी 2022 में 140986 करोड़ एकत्र किए गए

इस महीने में 1,42,095 करोड़ रुपये सकल जीएसटी राजस्व एकत्र

नईदिल्ली (आरएनएस)। मार्च 2022 महीने में एकत्र सकल जीएसटी राजस्व 1,42,095 करोड़ रुपये रहा जिसमें सीजीएसटी 25,830 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,378 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 74,470 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 39,131 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 9,417 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 981 करोड़ रुपये सहित) है। मार्च 2022 में कुल सकल जीएसटी संग्रह जनवरी 2022 के महीने में एकत्र किए गए 1,40,986 करोड़ रुपये के पूर्व के रिकॉर्ड को तोडक़र अब तक का सबसे अधिक है।

सरकार ने नियमित भुगतान के रूप में आईजीएसटी से 29,816 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 25,032 करोड़ रुपये एसजीएसटी का निपटारा किया। इसके अलावा, केन्द्र ने इस महीने में केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 50:50 के अनुपात में तदर्थ आधार पर आईजीएसटी के 20,000 करोड़ रुपये का निपटारा किया है। मार्च 2022 के महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व नियमित और तदर्थ निपटान के बाद सीजीएसटी के लिए 65646 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 67410 करोड़ रुपये है। केन्द्र ने महीने के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18,252 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा भी जारी किया।

मार्च 2022 के महीने में राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 15 प्रतिशत अधिक और मार्च 2020 में जीएसटी राजस्व से 46 प्रतिशत अधिक है। महीने के दौरान, माल के आयात से राजस्व 25 प्रतिशत अधिक था और राजस्व घरेलू लेन-देन से (सेवाओं के आयात सहित) पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से राजस्व की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। जनवरी 2022 (6.88 करोड़) के महीने में ई-वे बिलों की तुलना में, छोटा महीना होने के बावजूद फरवरी 2022 के महीने में ई-वे बिलों की कुल संख्या 6.91 करोड़ है, जो तेज गति से व्यावसायिक गतिविधि की वसूली का संकेत देता है।

वित्त वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.38 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में औसत मासिक संग्रह क्रमश: 1.10 लाख करोड़ रुपये, 1.15 लाख करोड़ रुपये और 1.30 लाख करोड़ रुपये रहा है। आर्थिक सुधार के साथ-साथ, कर चोरी-रोधी कार्यों, विशेष रूप से फर्जी बिल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, जीएसटी को बढ़ाने में योगदान दे रही है। राजस्व में सुधार क्रम बदलने के ढांचे को ठीक करने के लिए परिषद द्वारा किए गए विभिन्न दर युक्तिकरण उपायों के कारण भी हुआ है।

नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान दिखाता है। तालिका मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्र किए गए जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े दिखाती है।

नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा तीन दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे

नईदिल्ली (आरएनएस)। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर शुकवार को नयी दिल्ली पहुंचे । विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह जानकारी दी ।

बागची ने ट्वीट किया, एक विशेष मित्र का स्वागत । नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 1 से 3 अप्रैल तक अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे । विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जुलाई 2021 में पदभार संभालने के बाद देउबा की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी प प्रतिशती आरजू देउबा भी भारत आई हैं । विदेश मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया था कि नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल भी भारत आ रहा है। मंत्रालय ने कहा था, भारत और नेपाल के सदियों पुराने और मित्रतापूर्ण विशेष संबंध हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है। बयान के अनुसार, नेपाल के प्रधानमंत्री की आसन्न यात्रा दोनों देशों के बीच विविध क्षेत्रों में व्यापक 'द्विपक्षीय गठजोड़' में महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा करने और दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिये इसे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।

विदेश मंत्रालय ने बताया था कि देउबा का दो अप्रैल को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मिलने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का कार्यक्रम है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का शुक्रवार को यहां भाजपा कार्यालय आने का कार्यक्रम भी है।

कश्मीरी पंडितों के कातिल बिट्टा कराटे का केस 31 साल बाद फिर खुला, कोर्ट में 16 अप्रैल को होगी सुनवाई

श्रीनगर (आरएनएस)। श्रीनगर की एक सत्र अदालत ने 1990 के दशक में सशस्त्र विद्रोह के दौरान कश्मीरी पंडितों की हत्या के आरोपी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के खिलाफ मामला फिर से खोल दिया है। कोर्ट इस मामले पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में 2 फरवरी, 1990 को सतीश टिक्कू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टिक्कू के परिजनों की याचिका पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने यह एक्शन लिया है।

सतीश टिक्कू के बहनोई प्रदीप कौल ने कहा कि मामला विचाराधीन है, इसलिए परिवार टिप्पणी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है। इस मामले को लेकर मीडिया पहले ही हल्ला मचा चुका है। हम चाहते हैं कि चीजें कानून के अनुसार चले। दरअसल, कश्मीर फाइल्स फिल्म ने कश्मीरी पंडितों की हत्याओं और पलायन पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को काफी हद तक हिंसा का दोषी ठहराया गया है, जिसने एक स्वतंत्र कश्मीर की मांग की थी।

20 पंडितों को मारने की बात कराटे ने स्वीकार की- कराटे के साथ-साथ यासीन मलिक कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान से फंडिंग करने के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। एनआईए ने 2017 में कराटे और फरवरी 2019 में मलिक को गिरफ्तार किया। बिट्टा कराटे को शुरुआत में 1990 में गिरफ्तार किया गया था। उसने जेकेएलएफ नेताओं के आदेश पर 20 पंडितों को मारने की बात कैमरे पर स्वीकार की थी। बाद में कराटे ने इसका खंडन करते हुए कहा कि उसने दबाव में यह बयान दिया। 2006 में कराटे को सबूतों की कमी और अभियोजन पक्ष की अरुचि पर रिहा कर दिया गया था।

31 साल बीत गए, न्याय तो मिलना चाहिए- फारूक अहमद डार का नाम बिट्टा कराटे इसलिए पड़ा क्योंकि वह मार्शल आर्ट में ट्रेंड था। कराटे पुराने शहर श्रीनगर के गुरु बाजार इलाके में बड़ा हुआ, जो 1990 के दशक में उग्रवाद का केंद्र था। उसने हाई स्कूल छोड़ दिया, जिसमें कई पंडित शिक्षक थे। वकील उत्सव बैंस ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। 31 साल बीत चुके हैं और परिवार को नहीं पता कि मामले का क्या हुआ।

बनारस रेल इंजन कारखाना ने 367 रेल इंजन का उत्पादन कर बनाया रिकॉर्ड

नईदिल्ली (आरएनएस)। बनारस रेल इंजन कारखाना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक के सर्वाधिक रेल इंजनों का निर्माण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रचा इतिहास । इस वित्तीय वर्ष मोजाम्बिक को निर्यात 04 रेल इंजनों सहित कुल 367 रेल इंजनों का निर्माण किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । इन 367 रेल इंजनों में यात्री रेल इंजन डब्ल्यूएपी77 कुल 31, मालवाहक रेल इंजन डब्ल्यूएजी9 कुल 332 एवं मोजाम्बिक हेतु 04 रेल इंजन सम्मिलित हैं ।

साथ ही बरेका ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्यातीत लोको से 60.68 करोड़ एवं वर्ष 2011 से अब तक कुल 704 करोड़ तथा गैर रेलवे ग्राहकों से वर्ष 2011 से अब तक 1837 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की । वर्ष 2021-22 में बरेका ने निर्यातित रेल इंजनों के पूर्जों से 6.09 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की जो पिछले वर्ष 2020-21 में 1.08 करोड़ थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 464 प्रतिशत अधिक है । इसी प्रकार गैर रेलवे ग्राहकों से रेल इंजनों के पूर्जों के आपूर्ति से 16.4 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई जो पिछले वर्ष 2020-21 में 8.29 करोड़ थी, जो तुलनात्मक रूप से 98.6 प्रतिशत अधिक रहा ।

ज़िम्बाब्वे के राष्ट्रीय रेलवे के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का बनारस रेल इंजन कारख़ाना का दौरा: क्रैंक-केस असेंबली, जो रेल इंजन का सबसे महत्वपूर्ण आइटम है, इसे बरेका में इन-हाउस बनाया गया है। इन इंजनों को वर्तमान में कोयला खदानों से कोयला ढोने के लिए भिन्न-भिन्न इकाइयों में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।

इन इंजनों का उद्घाटन औपचारिक रूप से मोजाम्बिक के राष्ट्रपति ने 11 फरवरी 2022 को बीरा, मोजाम्बिक में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति और भारत के उच्चायुक्त की उपस्थिति में किया था। इस प्रकार बनारस रेल इंजन कारखाना एक भरोसेमंद भागीदार और लोकोमोटिव निर्माण ब्रांड के रूप में विश्व पटल पर आया । परिणामस्वरूप, मेसर्स राइट्स के अधिकारियों के साथ जिम्बाब्वे के राष्ट्रीय रेलवे की पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया।

महाप्रबंधक बरेका अंजली गोयल ने जिम्बाब्वे बोर्ड के अध्यक्ष एनआरजेड एडवोकेट मार्टिन तफारा दीन्हा, बोर्ड के सदस्य इलेश कुमार पटेल, महाप्रबंधक सुरेस्पिना जिन्नांडुको, ट्रैक्शन एंड क्वालिटी लवमोर कटोन्हा और क्षेत्रीय अभियंता त्सेत्सी एनडलोवु को बैठक के दौरान बधाई दी। राइट्स और उन्हें अपने निर्यात आदेशों को पूरा करने में पूर्ण समर्थन और मुस्तैदी का आश्वासन दिया। महाप्रबंधक बरेका ने ज़िम्बाब्वे की टीम को यह भी आश्वासन दिया कि बरेका ज़िम्बाब्वे के राष्ट्रीय रेलवे के आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक है। ज़िम्बाब्वे के राष्ट्रीय रेलवे की टीम ने बरेका में उपलब्ध निर्माण सुविधाओं को देखने के लिए दिनांक 29.03.2022 को बनारस रेल इंजन कारखाना का दौरा किया।

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्द की पहचान अभी नहीं हो पाई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि एक-दो और आतंकवादी यहां छिपे हो सकते हैं। घटनास्थल के आसपास लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।

पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने शोपियां के तुर्कवांगम गांव में घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि सुरक्षाबल के जवान जब एक विशेष क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तभी वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।

आईआरईडीए ने 3000 इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी को 268 करोड़ दिए

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) ने 3,000 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी के लिए 267.67 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है। ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी इस पूंका उपयोग 3,000 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए करेगी, जिससे इसके इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी। आईआरईडीए ने कंपनी को 267.67 करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋण में से 35.70 करोड़ रुपये की पहली किशत जारी की है। सहयोग के बारे में आईआरईडीए के सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने कहा, आईआरईडीए में हमारा मानना है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास की भारी संभावना है। ब्लूस्मार्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, और हम उनकी टीम का समर्थन करते हैं। इस क्षेत्र में और भारत को एक स्वच्छ और हरित देश बनाने की दिशा में यह हमारा पहला बड़ा निवेश है। आईआरईडीए देश में परिवहन को स्वच्छ स्रोतों तक ले जाने की प्रगति को गति देने के लिए और अधिक इलेक्ट्रिक वाहन परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करने की उम्मीद करता है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के कंपनी के प्रयास का हिस्सा है।

आईआरईडीए के बारे में:

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम मिनी र प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा विस्तार के लिए समर्पित भारत का अग्रणी वित्तीय संस्थान है। 1987 में अपनी स्थापना के बाद से, आईआरईडीए ने भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के सबसे बड़े हिस्से को वित्तीय सहायता प्रदान की है। आईआरईडीए ने अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए पिछले कुछ वर्षों में कुल 1,20,522 करोड़ (लगभग) रुपये की मंजूरी दी है और 77,946 करोड़ (लगभग) रुपये वितरित किए हैं और 31 मार्च, 2022 तक देश में 19,453 मेगावाट से अधिक आरई क्षमता का सहयोग किया।

ब्लूस्मार्ट के बारे में:

ब्लूस्मार्ट (एक स्टार्ट-अप) शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता के भारत के मार्ग के लिए काम कर रहा है, चालकों-भागीदारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहा है और ग्राहकों को भाड़े पर विश्वसनीय चालक सेवा प्रदान करना जारी रखे है। ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी ने दिल्ली एनसीआर में 350,000 से अधिक ऐप डाउनलोड के साथ 35 मिलियन से अधिक स्वच्छ किमी को कवर करते हुए 1 मिलियन ऑल-इलेक्ट्रिक ट्रिप पूरे किए हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

अरुणाचल और नागालैंड के कुछ जिले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों के क्षेत्रों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा के तहत छ: माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद इन्हें सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार नागालैंड में दीमापुर, न्यूलैंड, चूमुकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक, पेरेन, जुन्हेबोटो जिलों और कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण जुबाजा और केजोचो क्षेत्रों को आज से 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग, लांगडिंग तथा असम से लगते नामसाई जिले के कुछ क्षेत्रों को आज से आगामी 30 सितंबर तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही ऐलान किया था कि नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों के दायरों में कमी करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार : औरंगाबाद के छात्रों ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया

पटना (आरएनएस)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए, जिसके अनुसार 77.88 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। औरंगाबाद के छात्रों ने शीर्ष 10 की सूची में चार जगह लेकर बोर्ड परीक्षा में अपना दबदबा बनाया। परीक्षा समाप्त होने के 34 दिन बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने परिणाम घोषित किए। बीएसईबी के एक अधिकारी के अनुसार, 16,11,099 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 12,86,971 उत्तीर्ण हुए। औरंगाबाद जिले के नक्सलवाद प्रभावित दाउद नगर की मूल निवासी रामायणी राय ने राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने 500 में से 487 अंक हासिल किए, इसके बाद नवादा की सानिया कुमारी और मधुबनी के विवेक ठाकुर (486/500) संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। सानिया नवादा जिले के रजौली प्रखंड के एक मिठाई विक्रेता की बेटी हैं। औरंगाबाद की एक अन्य छात्रा प्रज्ञा ठाकुर ने 485 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। औरंगाबाद के शंभू कुमार और तृप्ति राज क्रमश: 481 और 479 अंकों के साथ राज्य में सातवें और नौवें स्थान पर रहे।

अरविंद केजरीवाल के घर उपद्रव मामला : हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 सप्ताह में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कथित तोडफ़ोड़ और उपद्रव की एसआईटी से जांच की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने याचिका का विरोध किया था। पुलिस ने कहा कि वह मामले की जांच कर रही है, इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम आपको जांच से रोक नहीं रहे हैं आप अपनी जांच कीजिए और स्टेटस रिपोर्ट पेश कीजिए। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने पंजाब में हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भी वायरस नामक संगठन ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने यह दलील तब दी जब याचिका दाखिल करने पर सवाल उठाया गया। आम आदमी पार्टी (आप) विधायक सौरभ भारद्वाज ने इस घटना की एसआईटी से जांच की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पुलिस ने मामले में नोटिस जारी नहीं करने का आग्रह करते हुए पहले से कहा था कि वह सीलबंद जांच रिपोर्ट पेश करेगी। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि सभी सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।